उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

B.P.L.E. APPEAL No.- 109/2011-12

Appellant - Vig English School, through Secretary Sri Hare Ram Singh, S/o Late Chandrama Singh

- Vrs.-

Respondent/O.P. State of Jharkhand

	आदेश	
	1. यह अपील आवेदन अंचल अधिकारी का न्यायालय जमशेदपुर द्वारा B.P.L.E. केस नम्बर–70/2011–12 में दिनांक 01.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Vig English School, through Secretary Sri Hare Ram Singh, S/o Late Chandrama Singh द्वारा दायर किया गया है। अपीलार्थी Vig English School, through Secretary Sri Hare Ram Singh, S/o Late Chandrama Singh द्वारा अपील आवेदन में जिक्र किया गया है, कि "(1) That the B.P.L.E. Case No. 70 of 2011-12 was initiated by the Respondent against the Appellant with respect to land measuring 3.21 acre being Plot No. 36, Khata No. 239, Thana No. 1193, within Mouza Khakripara, District East Singhbhum. (2) That in the said BPLE Case no notice was ever served upon the Appellant. (3) That as no notice was ever served upon the Appellant, the Appellant could not take appropriate step before the court below. (4) That on 23.12.2011 the Court below passed an exparte order, wherein and whereunder the Appellant was directed under section 6(2) of the BPLE Act, to comply with the order within 06.01.2012." अपील आवेदन के Ground के कंडिका (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) एवं (xi) में जिक्र किया गया है कि "(ii) For that the learned Court below has failed to appreciate the provisions of Section 3 Sub-Section 1 of the B.P.L.E. Act and has erroneously passed the impugned order in contravention of the same without giving chance to the Appellant to file its show-cause. (iii) For that the learned Court below has passed the impugned order against the principle of natural justice. (iv) For that the learned Court below should have given an opportunity to the Appellant by conducting, inquiry as to whether the notice has been served upon the Appellant or not. (v) For that the learned Court below has incorrectly passed the impugned order without considering, the fact that the Appellant is a school and is in occupation of the land in question for more then thirty years. (vi) For, that the learned Court below was desperate in passing, the impugned order which is evident from the record itself. (vii) For that the learned Court below has failed to appreciate that	

7/6/16

the alleged encroached land has been in occupation of the Appellant School from a pretty long time. (viii) For that a B.P.L.E. Case being Case No. III/1/9/93-94 was already initiated earlier by the C.O. Jamshedpur. In the said case vide order dated 18.12.1995 the learned C.O. Jamshedpur referred the matter to higher authority and recommended to grant the land on lease. (ix) For that the Appellant applied before the court of Deputy Commissioner (Land Reform) for allotment/leasing of the land in question to the school and the said court vide its order dated 19.11.1999 referred the matter for inquiry and needful and also recommended the case. (x) For that there after the case record was misplaced either in the court of the D.C.L.R. or in the office of the A.D.C. for final order which is still sub-judiced. (xi) For that the learned Court below has failed to appreciate that the Appellant has perfected its right, title and interest over the proceeding land by remaining in peaceful occupation/possession of the same for a period much more then the statutory period.

2. निम्न अदालत अभिलेख बी0पी0एल0ई0 वाद संख्या–70/2011–12 में दिनांक 23.12.2011 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनाबाद बिहार (झारखण्ड) की भूमि पर मकान बनाकर अवैध रूप से अतिकमण किया गया है। अतिकमणकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। विपक्षी को सेक्शन 3 के तहत नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अतिकमणकारी के द्वारा दिनांक 08.11.2011 को निर्धारित तिथि को अपना पक्ष नहीं रखा गया है। विपक्षी के द्वारा कोई भी ऐसा सबूती कागजात पेश नहीं किया गय ा है जिसके आधार पर प्रमाणित हो सके कि मौजा–खाकड़ीपाड़ा, वार्ड/थाना नं0–1193, खाता नं0–239, प्लॉट नं0–36, रकवा– 3.21 एकड़ भूमि का स्वामित्व बनता है। अतिकमणकारी के द्वारा अवैध रूप से अनाबाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के कुल 3.21 एकड़ भूमि पर मकान बनाकर अतिकमण कर लिया गया है। यह भूमि अनाबाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि है तथा बिहार लोक भूमि अतिकमण अधिनियम के अन्तर्गत बी0पी0एल0ई0 एक्ट की धारा–2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत है। अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिकमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिकमण अधिनियम 1956 की धारा–6(2) के अन्तर्गत अतिकमणकारी महेश विग, हरेराम सिंह, पिता–स्व0 लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, सा0–खाकड़ीपाड़ा को उच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिकमणकारी को नोटिस करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अतिकमण दिनांक 05.08.2015 तक हटा लें अन्यथा बलपूर्वक अतिकमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिकमणकारी से वसूली जाएगी।"

3. निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है, कि "प्रश्नगत भूमि मौजा–खाकड़ीपाड़ा, वार्ड/थाना नं0–1193, खाता नं0–239, प्लॉट नं0–36, रकवा– 3.21 एकड़ भूमि अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। अतिकमणकारी द्वारा चारदिवारी निर्माण कर अतिकमण किया जा रहा है। अतः अतिक्रमण दायर कर अतिकमण हटाने की कृपा की जाय।"

4. अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित

कागजातों की छायाप्रति समर्पित किया गया है :–

(i) अभीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद की छायाप्रति,

(ii) अभीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का Sale Deed की छायाप्रति,

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश, निम्न अदालत अभिलेख में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–84(1), (2) एवं (3) में प्रावधानित है, कि (1) In any suit or other proceedings in which a record-of-rights prepared and published under this Chapter or a duly certified copy thereof or extract therefrom is produced, such record-of-rights shall be presumed to have been finally published unless such publication is expressly denied and a certificate, signed by the Revenue-officer, or by the Deputy Commissioner of any district in which its local area, estate or tenure or part thereof to which the record-of-rights relates is wholly or partly situate, stating that the record-of-rights has been finally published, under this chapter shall be conclusive evidence of such publication. (2) The (State) Government may, by notification, declare with regard to any specified area, that a record-of-rights has been finally published for every village included in that area; and such notification shall be conclusive evidence of such publication. (3) Every entry in a record-of-rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct until it is proved, by evidence, to be correct. इन प्रावधानों के अनुसार record-of-rights का निर्धारण हाल सर्वे खतियान के आधार पर की जानी है। हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट है, कि निम्न न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायसंगत है इसे यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 07.06.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

7/6/16

उपायुक्त

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

7/6/16

उपायुक्त

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।